"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2004—फाल्गुन 29, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से. (1990), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त उद्योग तथा प्रबंध संचालक सी. एस. आई. डी. सी. को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (Chips) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

2. श्री पाठक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993) संयुक्त सचिव, आई.टी. एवं बायोटेक्नोलॉजी, वित्त विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, Chips, संचालक, संस्थागत वित्त, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, 12वाँ वित्त आयोग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (Chips) के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्रीमती इंदिरा मिश्र, भा.प्र.से. (1969), अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग एवं समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से. (1973), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (1979), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नालॉजी विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से. (1986), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. के. के. चक्रवर्ती, भा.प्र.से. (1970) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-3/2004/1/2.—श्री आर. पी. बगाई, भा.प्र.से. (1970) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं आयुक्त, परिवहन को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं आयुक्त, परिवहन के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है. श्री बगाई को पदोन्नति का लाभ दिनांक 8 मार्च 2004 से प्राप्त होगा.

2. श्री आर. पी. बगाई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3 (ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/16/2003/1/2 दिनांक 27-1-2004 के अनुक्रम में श्री एम. एस. पैकरा, भा.प्र.से. (1991) को संयुक्त सचिव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा (स्कूल) विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री ए. के. विजयवर्गीय भा.प्र.से. (1969) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को तत्काल प्रभाव से अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के कार्यभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री डी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. (1982), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आबकारी आयुक्त तथा पदेन सचिव, वित्त एवं योजना विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ पदस्थ किया जाता है.

2. श्री चंद्रहास बेहार, भा.प्र.से. (1988) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक एफ-02-10/2004/1-8.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को तत्काल प्रभाव से, उसी हैसियत में वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ-2-1./01/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9-10-2003 द्वारा श्री गिरीशचन्द्र बाजपेयी को स्थानापन्न सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री बाजपेयी को सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के स्थान पर प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2004

क्रमांक 627/2004/1-8/स्था.—श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 19-1-2004 से 24-1-2004 तक 6 दिन का लघुकृत अंवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25 जनवरी, 2004 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाय. एस. बेले अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 631/2004/1-8/स्था.—श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 6-2-2004 से 19-2-2004 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा, उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 633/2004/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग को दिनांक 10-12-2003 से 26-12-2003 तक 17 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी को संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो वि. क. अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 635/2004/1-8/स्था.—श्री विपिन मांझी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, गृह विभाग को दिनांक 31-12-2003 से 9-1-2004 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विपिन मांझी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी को गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विपिन मांझी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 637/2004/1-8/स्था.—श्री कमल राज मिश्रा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 30-12-2003 से 16-1-2004 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2004 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमल राज मिश्रा, उप सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल राज मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2004

क्रमांक 694/676/2004/1-8.—श्री देवाशीष दास (भा. व. से.) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, बायो-टेक्नालॉजी (खनिज एवं उद्योग विभाग) की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से वन विभाग को वापस लौटाई जाती है. श्री दास अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के पद का कार्य अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् देखते रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 1903 एफ 13-166/गृह-दो/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक एफ 1-91-बी-1-दो भारत के संविधान के अनुच्छेद 302 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सेना (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 की अनुसूची-चार (1) के कालम (3) में दर्शित जिला सेनानी से संभागीय सेनानी के पद पर पदोन्नति करने हेतु उल्लेखित 10 वर्ष के सेवा अनुभव में 2 (दो) वर्ष की एक बार के लिए विशेष छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मण्डावी, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 15-138/2002/नौ/17.—फार्मेसी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 26 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर 2003 की कंडिका-3 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. ए. कदीर, को छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद से कार्यमुक्त करते हुये, डॉ. आर. आर. तिवारी, उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 21-3/2003/नौ/55.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2003 में, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का क्रमांक 14) द्वारा मूल अधिनियम में अंत:स्थापित धारा 16क की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पर्यवेक्षक मंडल में रिक्त हुए पदाधिकारी क्रमांक 7, 8 एवं 9 के स्थान पर निम्नानुसार सदस्य नामांकित करता है.

1. सुश्री पिंकी ध्रुव, विधायिका, सिहावा - सदस्य
2. सुश्री लता उसेंडी, विधायिका, कोण्डागांव - सदस्य
3. सुश्री रमशीला साहू, विधायिका, गुंडरदेही - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक/डी-812/2717/आजाक/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आदेश क्रमांक डी-1932/2717/आजाक/2001, रायपुर दिनांक 12-7-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिये श्री इकबाल अहमद रिजवी-अध्यक्ष, श्री रंजन दयाल-सदस्य तथा श्री राजेन्द्र सिंह बेनीपाल-सदस्य की, की गयी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. दलेई, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 11-10/16/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा-8 ''ए'' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे अनुसूची (टेबल) के कॉलम-3 में दर्शित अधिकारियों को कॉलम-4 में दर्शाए गये स्थान पर अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

परन्तु यह अधिकारी इन श्रम न्यायालयों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी की हैसियत से केवल वही न्यायिक कार्य संपादित करेंगे जो राज्य शासन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा समय-समय पर प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकृत करने हेतु सौंपा जाता है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विद्यमान श्रम न्यायालयों के नाम (2)	वर्तमान पीठासीन अधिकारियों के नाम (3)	स्थान जहां पर अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे (4)
1.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री समारूलाल मात्रे	श्रम न्यायालय, रायपुर
2.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री एस. के. त्रिपाठी	श्रम न्यायालय, रायपुर

Raipur, the 23rd February 2004

No. F 11-10/16/2003.—In exercise of powers conferred by section 8-A of Chhattisgarh, Industrial Relation Act, Govt. of Chhattisgarh hereby appoits, officers shown in col. III, as additional Presiding Officer for the place as shown in col. IV.

Provided that these officers will perform the Judicial work as additional Presiding Officer for this Labour Court only as per directions of State Government, Chhattisgarh, Raipur, issued from time to time and will hear and decide the cases which have been made over to them.

TABLE

Sl. No. (1)	Names of the Existing Labour Courts (2)	Names of the Present Presiding Officer. (3)	Place where Addl. Presiding Officer is posted (4)
1.	Labour Court, Ambikapur	Shri Samaroo Lal Matre	Labour Court, Raipur
2.	Labour Court, Raigarh	Shri S. K. Tripathi	Labour Court, Raipur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट हांग्डोला, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 4-30/16/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स एसोसियेटेट सीमेन्ट कंपनी जामुल सीमेंट वर्क्स दुर्ग को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1-11-2000 से 15-9-2001 तक इस शर्त पर छूट देता है कि वर्तमान चिकित्सीय सुविधाओं के स्तर में किसी भी स्थिति में कमी नहीं होगी, वरन इन्हें और उन्नत किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 4-30/16/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स एसोसियेटेट सीमेन्ट कंपनी जामुल सीमेंट वर्क्स दुर्ग को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 16-9-2002 से 15-9-2003 तक इस शर्त पर छूट देता है कि वर्तमान चिकित्सीय सुविधाओं के स्तर में किसी भी स्थिति में कमी नहीं होगी, वरन इन्हें और उन्नत किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 4-30/16/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स एसोसियेटेट सीमेन्ट कंपनी जामुल सीमेंट वर्क्स दुर्ग को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 16-9-2003 से 15-9-2004 तक इस शर्त पर छूट देता है कि वर्तमान चिकित्सीय सुविधाओं के स्तर में किसी भी स्थिति में कमी नहीं होगी, वरन इन्हें और उन्नत किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 10-2/2003/20.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-3-2003 द्वारा राजेश्री महंत श्री रामसुन्दर दास जी, रायपुर को राज्य शासन द्वारा संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था. राजेश्री महंत रामसुन्दर दास का त्यागपत्र अध्यक्ष पद से स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चिन्तामणि सिंह, श्रीकोट आश्रम कुसमी सरगुजा को राज्य संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष पद हेतु मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 6-91/2003/वा. कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नांकित सहायक आयुक्तों को उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करता है एवं उन्हें उनके नाम के सामने कॉलम 4 में दर्शायेनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पद (2)	वर्तमान पदस्थापनां (3)	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना (4)
1.	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर, सहायक आयुक्त.	कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग, रायपुर.	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
2.	श्री एल. आर. राजपूत सहायक आयुक्त.	कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग, रायपुर.	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर.
3.	श्री के. एस. बरिहा सहायक आयुक्त.	कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग संभाग, दुर्ग.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग संभाग, दुर्ग.
4.	श्री जे. आर. भगत सहायक आयुक्त.	कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग, रायपुर.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर.
5.	श्री आर. के. मेश्राम सहायक आयुक्त.	कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग, रायपुर.	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग.

2. (i) पदोन्नत अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प देना होगा कि :—

(क) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद के वेतनमान में वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूलभूत नियम 22-डी के अंतर्गत उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

अथवा

(ख) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूलभूत नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित कर दिया जाये और दूसरी बार सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के वेतनमान में वेतन-

वृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूलभूत नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाये.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

3. इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूलभूत नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का संज्ञान है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2004

क्रमांक 86/13/2004/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारियों के लेखे, उक्त अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे :—

अनुसूची
[धारा 4 (1) देखिये]

1. समस्त नगर पालिका निगम,
2. समस्त नगर पालिका परिषद्,
3. समस्त नगर पंचायतें,
4. समस्त जिला पंचायतें,
5. समस्त जनपद पंचायतें,
6. समस्त ग्राम पंचायतें,
7. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन समस्त कृषि उपज मंडी समिति,
8. समस्त प्राधिकारी जो किसी नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार हो या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये गये हों.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2004

क्रमांक 86/13/2004/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 86/13/2004/स्था./चार, दिनांक 5 फरवरी, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 5th February 2004

No. 86/13/2004/estt./IV.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (43 of 1973), and in supersession of all previous notifications issued on the subject, the State Government, hereby declares that the accounts of the Local authorities specified in the Schedule below shall be subject to audit under the said Adhiniyam :—

SCHEDULE
[See Rule 4 (1)]

1. All Municipal Corporations,
2. All Municipal Councils,
3. All Nagar Panchayats,
4. All Zila Panchayats,
5. All Janpad Panchayats,
6. All Gram Panchayats,
7. All market Committees constituted under the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973),
8. All authorities Legally entitled to, or entrusted by the State Govt. with the control or management of a Municipal or Local Fund.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2004

क्रमांक 87/13/2004/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त निगमित तथा अनिगमित निकायों को लागू होंगे.

अनुसूची
[धारा 21 (3) देखिये]

(क) राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित की गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय तथा उनके संघटक महाविद्यालय—

1. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.

2. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.
3. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर.
4. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़.
5. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर.

(ख) छत्तीसगढ़ बोर्ड—

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर.
2. बोर्ड ऑफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडीसिन, छत्तीसगढ़.
3. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीन समस्त समितियां.

(ग) न्यास निधियां—

1. दुधाधारी वैष्णव न्यास निधि, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर.
2. राय बहादुर जगन्नाथ राव दानी ट्रस्ट फण्ड, रायपुर.
3. राय साहेब जगन्नाथ तिवारी ट्रस्ट फण्ड, रायपुर.
4. राजगामी संपदा निधि, राजनांदगांव.
5. रानी सूर्यमुखी देवी गोल बाजार ट्रस्ट फण्ड, राजनांदगांव.
6. माफी टेम्पल ट्रस्ट, जगदलपुर.
7. बोर्ड ऑफ वाइस भरतचंद भंजदेव ट्रस्ट फण्ड, जगदलपुर.
8. माफी टेम्पल ट्रस्ट स्टेट, दन्तेवाड़ा.
9. मां सिंहवाहिनी मंदिर ट्रस्ट, कांकेर (बस्तर).

(घ) राज्य सरकार की सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली समस्त गैर सरकारी, शैक्षणिक तथा तकनीकी संस्थाएं.

(ङ) अन्य संस्थाएं—

1. निजी पॉलिटेक्निक्स.
2. छत्तीसगढ़ कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर.
3. मुख्य मंत्री सहायता कोष के लेखे.
4. संचालक स्थानीय निकाय के कार्यालय में स्थापित पेंशन फण्ड.
5. संचालक स्थानीय निकाय के कार्यालय में स्थापित टेक्निकल फण्ड.
6. रोगी कल्याण समिति.
7. जिला शहरी विकास अभिकरण.
8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2004

क्रमांक 87/13/2004/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 87/13/2004/स्था./चार, दिनांक 5 फरवरी, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 5th February 2004

No. 87/13/2004/estt./IV.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam. 1973 (43 of 1973), the State Government, hereby directs that the provisions of the said Adhiniyam shall apply to all corporate and non-corporate bodies specified in the Schedule to the said Adhiniyam.

SCHEDULE
[See Section 21 (3)]

(A) Universities established by or under any law enacted by the state Legislature and their constituent colleges—

1. Pt. Ravishankar University, Raipur.
2. The Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidhyalaya, Raipur.
3. Guru Ghasidas Vishwa Vidhyalaya, Bilaspur.
4. The Indira Kala Sangeet Vishwa Vidhyalaya, Khairagarh.
5. The Bastar Vishwa Vidhyalaya, Jagdalpur.

(B) Chhattisgarh Boards—

1. The Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal, Raipur.
2. The Board of Homeopathic and Bio-Chemic System of Medicine, Chhattisgarh.
3. The Rajya Vidhik Sewa Pradhikaran and all Sub-ordinate Councils.

(C) Trust Funds—

1. The Dudha Dhari Vaishnav Nyas-Nidhi Sanskrit Mahavidhyalaya, Raipur.
2. The Raya Bahadur Jagannath Rao Dani Trust Fund, Raipur.
3. The Rao Saheb Jagannath Tiwari Trust Fund, Raipur.
4. The Rajgami Sampda Nidhi, Rajnandgaon.
5. The Rani Surya Mukhi Devi Golbazar Trust Fund, Rajnandgaon.
6. The Mafi Temple Trust, Jagdalpur.
7. The Board of Vice Bharat Chand Bhanjdeo Trust Fund, Jagdalpur.
8. Mafi Temple Turst State, Dantewada.
9. Maa Singha Vahini Mandir Trust, Kanker (Bastar).

(D) All Non Government Educational and Techinical Institutions Receiving Grants-in-aid from the State Government.

(E) Other Bodies—

1. Private Polytechnics.
2. Chhattisgarh Agriculture Marketing (Mandi) Board, Raipur.
3. Accounts of Chief Minister Relief Fund.

4. Pension Fund established in the office of the Director of Local Bodies, Raipur.
5. Technical Fund established in the office of the Director of Local Bodies, Raipur.
6. Rogi Kalyan sammittee.
7. District Urban Development Agency.
8. Capital Area Development Authority, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2004

क्रमांक 105/47/ऊर्जा/03.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 (ए) तथा (सी) के प्रावधान के अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. इस स्थिति के प्रकाश में राज्य शासन श्री वाय. एन. जौहरी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को 1 फरवरी, 2004 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 6 माह, जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त करता है. नियुक्ति अवधि में सेवाशर्तें वही होंगी, जो मण्डल के अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के सदस्य की नियुक्ति के लिए पूर्व में निर्धारित की गई है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 203/47/ऊर्जा/03.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. इस स्थिति के प्रकाश में राज्य शासन सर्वश्री बी. के. शर्मा, मुख्य अभियंता (पारेषण एवं वितरण) तथा बी. आर. एस. बघेल, मुख्य अभियंता (उत्पादन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को अन्य आदेश तक क्रमशः सदस्य एवं सदस्य (उत्पादन परियोजना), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है. नियुक्ति अवधि में सेवाशर्तें वही होंगी जो पूर्व में मण्डल में कार्यरत अधिकारियों के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. बंजारे, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2003

क्रमांक/एफ-73-136/03/उ.शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 (3) के अधीन एक्वाटेक यूनिवर्सिटी, रायपुर के कुलपति द्वारा धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत अध्यादेशों को सहमति प्रदान करती है तथा छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 की उपधारा (4) द्वारा 05 (पांच) "प्रथम अध्यादेशों" को अनुमोदित करती है.

ये अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

ORDINANCE NO. - 1

Admission of Students of the University and their enrolment
(Section 27 (1) (a) of the Adhiniyam)

1. In this Ordinance unless there is anything contrary to Statute and the Adhiniyam

   (a) "Qualifying examination means an examination the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelors, Masters, M.Phil., Doctorate, Degrees, Diplomas or Certificates conferrable by the University.

   (b) 'Compartment' or 'Supplementary' means a result in which a student has been declared fail in ONE subject by the concerned examining body i.e. a recognized Board of Secondary Education e.g. CBSE, ICSE, State, Board of Secondary Education etc. Such a student may be declared pass if he/she secures required percentage of marks in the examination held subsequently by the same examining body and declared Pass.

   (c) "Equivalent examination" means an examination conducted by

   (i) Any recognized Board of Secondary Education or
   ii) Any Indian or Foreign University or awarding body recognized by this University.

   (d) 'Gap period' means the period between the last date of attending the educational institution (excluding coaching institutes) and the date of taking the admission in the University.

2. The student seeking admission to the Pass/Hons. Degree/ Diploma courses of the University or schools/college institutes recognized and/or affiliated to the University and the Study Centres shall submit the application on prescribed form on or before last date of submission of such form, along with necessary certificates.

3. The admission committee will screen the applications and eligible candidates will be awarded provisional admission. An entrance test for admission may be prescribed for certain courses by the Academic Council.

4. Admission will be offered on rolling basis in an academic year as prescribed by the Academic Council.

5. The Student shall within a month of his admission submit certified copies of:

I. Character certificate from the Principal of the School/College last attended
II. Evidence of the Date of Birth
III. Statement of marks of the qualifying examinations / certificate of having passed the qualifying examination if marks criteria is not applicable.
IV. Medical certificate certifying physical fitness
V. Transfer Certificate and Migration certificate, wherever applicable.
VI. Any other document which may be felt as necessary to grant admission or to evidence any fact declared.

The admission is subject to the submission of these certified documents. If any of these are found to be forged tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled.

6. A student who has passed a part of any degree or diploma from another University/ awarding body shall be admitted to subsequent higher class for such examination in any institution / centre after its equivalence has been determined by the Academic Council.

7. A student with "Compartment/Supplementary" result may be granted 'Provisional' admission to any of the courses of study to which he / she would have otherwise normally been admitted if he / she had secured clear pass grades.

Provided that a provisionally admitted student submits the statement of marks after passing in the qualifying examination before declaration of the semester / year end result. In that case his/her result will not be withheld.

Provided that a student admitted provisionally fails to pass in the qualifying examination, his/her admission shall be terminated irrespective of the results in the University examination and the fee paid shall not be refunded.

8. A student who desires to be admitted after a gap period of one year or more shall along with his application for admission submit an affidavit duly notarized, justifying the reasons of gap period and certifying that he/she had not taken admission in any other college and. had not been rusticated or had not been sentenced to jail for a criminal offence or any other fact disqualifying him from taking admission.

9. A person who is, under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University / institution will not be admitted to any course of study in this University and its institutions / centers during the period of rustication or disqualification.

10. The admission of the students shall be completed within a month of commencement of each course, every year of the date decided by the Academic Council.

Provided that where the dates specified or the dates decided by the Academic Council, as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day will be the last day of admission.

Provided further that the Vice-Chancellor shall have the powers to grant admission in cases of genuine hardship beyond the last date of admission as given above on the clear understanding that the attendance of all such students shall be counted from the date of commencement of the course.

11. The Student shall get automatically enrolled as a member of the University as soon as he / she is admitted and pays all the dues together with the prescribed fee for enrolment and submits migration certificate wherever required.

ORDINANCE NO. - 2

Course of study to be laid for all degrees, diplomas and certificates
(Section 27 (I) (b) of the Adhiniyam)

1. There shall be a 'Board of Study' for every course or group of courses as decided by the Academic Council.

2. Each Board shall consist of the following members nominated by the Vice-Chancellor

   i. Professors of University Teaching Departments and Schools of Studies or Institutes in subjects for which it is constituted.
   ii. Two Heads of College Departments from the Colleges, Study Centers teaching the said subjects up to the postgraduate/ degree level, to be nominated by the Vice Chancellor by rotation
   iii. One Reader from the University Teaching Department and School of Studies teaching the said subjects to be nominated by the Vice Chancellor by rotation according to seniority,
   iv. Not more than two teachers in the said subject to be nominated by the Vice Chancellor.
   v. Five members to be co-opted, four of whom shall be experts from outside the University, and shall be from a recognized teaching research Institute or corporate experts in the subject under the faculty for which the Board is constituted.

3. The Chairman of the Board of Studies shall be nominated by the Vice Chancellor from amongst the members of the board referred to in subsection (2) above.

4. The term of the board of studies shall be two years

5. Pending the constitution of Board of Studies, the Vice Chancellor by an order can change the subject or subjects from one faculty to another and can perform other functions vested in the board of studies.

6. Besides that, as the need may be the Vice Chancellor can constitute a Provisional Board of Studies and assign a new subject in the faculty, which may be popular and in demand in other states and Universities in order to benefit the students of this University.

   Note: The Designation Professor, Reader, Lecturer is synonymous with Professor, Reader/ Associate Professor, Lecturer/ Assistant Professor. The Board shall be constituted by the Vice Chancellor based on need and requirement of the University.

7. The curriculum shall be forward looking, student centric and shall be so framed that it clearly lays down the 'learning outcomes', which every student must attain. It shall focus on imparting not only the knowledge and concepts but skins and competencies too. Adequate application oriented exercises and live projects shall constitute the syllabus.

8. It shall identify the text / reference books, journals, websites, CD-ROMS, case history, etc. which will enhance the learning standards of the student.

9. The Academic Council shall lay down the subjects that a student shall study leading to the award of certificates, diplomas and degrees by the University.

ORDINANCE NO. -3

The Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions
(Section (27)(1) (c) of the Adhiniyam)

1. The candidate after passing the examination prescribed for a particular certificate diploma or degree shall become eligible for the award of said certificate, diploma or degree respectively, as the case may be.

2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of Certificate, Diploma or Degree before the Academic Council soon after the declaration of the results. On being approved by the Academic Council, the Certificate and Diplomas shall be issued to the respective candidates by the Registrar.

3. The Certificates and Diplomas shall be signed by the Registrar.

4. The approval accorded by the Academic Council for the award of the respective degrees shall be placed before the Board of Management for its concurrence. On being concurred by the Board of Management, the Degree shall be awarded to the successful candidates at the convocation.

   Provided that if the candidate is in urgent need of the degree and the convocation is likely to be delayed, the degree may be given to him/her by the Vice-Chancellor on the payment of fee as may be prescribed by the University from time to time.

5. Degrees will have the same nomenclature as of UGC but University will be empowered to grant Diplomas of its own nomenclature.

6. The nomenclature of the programs that would be conferred by the University under different Colleges/ Schools shall be in following streams:

   i) Information Technology
   ii) Nursing
   iii) Pharmacy
   iv) Science (including Bio-technology)
   v) Education
   vi) Engineering & Technology
   vii) Medical Science
   viii) Commerce! Management
   ix) Maritime Education
   x) Insurance
   xi) Paramedical
   xii) Arts (including language)
   xiii) Any such other faculties prescribed by the Governing Body from time to time

   The degrees-masters/ bachelors or diplomas shall be awarded for completion of the courses.

   The Programs may get further bifurcated on the basis of sub streams and majors.

7. The University may establish as many additional schools and colleges imparting educating in specified fields as may be necessary to meet the requirements emerging through new areas of studies.

8. The programs/ courses in which approval of specific regulatory body or council is required will he offered after getting such approval/ permission.

9. The programs may be offered either by physical mode or in correspondence/ distance learning.

ORDINANCE NO. - 4

The Conditions of The Award of Fellowships and Scholarships
(Section 27 (1) (d) of the Adhiniyam)

1) Every year the University shall invite application through notifications for the awards to be made for Fellowships, Scholarships and student's Scholarships.

2) Subject to the general conditions applicable to all Fellowships and Research Scholarships as laid down in paragraph 4 below, the value, duration and conditions for the award of University Grants Commission Fellowships shall be such as are laid down by the University Grants Commission.

3) The value and duration of Scholarships/Fellowships Instituted by the University shall be laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management. The Selection of the candidate shall be made in accordance with the regulations laid down by the Board of Management from time to time.

4) Graduate and Postgraduate scholarships instituted by the University shall ordinarily be tenable for two academic sessions i.e. twelve months in the first year and ten months in the second year on condition that the scholarship holder produces a certificate of efficiency in studies from the Head of the Department in the subject of study.

5) The scholarship shall be tenable from the date on which the candidate joins the course or from the date specified to him in the award letter.

6) A scholarship shall be withdrawn in the subsequent year if the scholarship holder fails to secure at least 70% marks in the previous examination of the concerned course.

7) If a scholarship- holder is unable to appear at the previous examination on account of sickness or any other reasonable cause the student shall be paid only if the Head of the Institution certifies that the scholar diligently studied for the examination but was unable to take the examination for reasons beyond control. Such a student shall not receive scholarship during the next session but shall be entitled to the scholarship for the subsequent year if the scholar passes the previous examination with the requisite standard in the succeeding year in the first attempt.

8) A scholarship - holder shall at all times be of good behaviour and observe all rules of discipline.

9) (A) A Scholarship shall be liable to termination, if -

i. The scholarship-holder discontinues studies during the middle of the session.

ii. The scholarship-holder after he has been given a reasonable opportunity to explain his conduct is in the opinion of the Academic Council guilty of a breach of para 8 of this ordinance and if the Academic Council so directs, the scholarship-holder shall also be liable to refund the amount of scholarship drawn by him.

(B) The order of termination passed by the Academic Council shall be final.

ORDINANCE NO. - 5

Conduct of Examination
(Section 27 (1) (e) of the Adhiniyam)

Definitions

University Student means a student enrolled in any college/school of the University, enrolled in any college/school recognized and affiliated to the University, admitted to Distance Education Centres and Study Centes, etc. of the University.

Regular Candidate means a student who has pursued the course of study in a school/ college and seeks to take examination of the University as such.

Methods of Computing the Attendance

a) Attendance at lectures delivered and practical / clinicals / sessions if any, held during the academic session shall be counted.

b) Attendance at N.C.C./ N.S.S. Camp, outdoor assignments, etc. during the session shall be taken as full attendance at lectures / practicals on each such day of the camp and / or assignments and the days of journey to such camp/assignments.

c) Participation as a member of the University team in any Inter University competition shall be taken as full attendance for the day of participation in such competition.

d) For special reasons such as prolonged illness, deficiency in percentage of attendance not exceeding fifteen percent of the total number of lectures delivered and practicals/ clinicals / sessionals held in each subject can be condoned in writing by the Vice - Chancellor.

1. The students evaluation for award of all degrees/diplomas/certificates comprises the following.
   (a) Assignments
   (b) Examination

2. The weightage for the foregoing shall be as prescribed for each discipline and approved by the Academic Council.

3. Assignments

   a) The issue, submission and evaluation of assignments will be the responsibility of the Deans of respective colleges/schools. He shall maintain complete honesty in preparation and evaluation of assignments.

b) The entire class shall be divided in study groups.

c) Each study group will be given a separate assignment.

d) Minimum assignments per subject per semester to be given to the students shall be decided by Academic Council.

e) Each student will be required to defend his assignment after submission through a process of presentation/viva-voce etc.

f) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time specific to colleges and schools.

g) Students will be required to submit the assignments within two weeksfrom the date of issue/ any other time frame specified by the lecturer.

h) Assignments submitted after the, due date 'will not be assessed for more than 50% marks.

4. Examination

a) .The examination shall be the responsibility of the Dean of respective College/School. He shall maintain total academic honesty in the conduct of these examinations.

b) The examination shall be held on completion of formal teaching.

c) The practical examinations, where applicable, shall be held and be given a weightage as per the directions of the Academic Council.

5. Results of Assignment and Examination

The result of assignments and examination shall be submitted to the Controller of Examinations for evaluation.

6. Arrangement of Examination

All arrangements for the conduct of examination shall be made by the Controller of Examinations (sub-Registrar Evaluation) in accordance with such directions as may be issued by the Board of Management in consultation with the Academic Council.

7. The Controller of Examinations shall finalize the date of examination.

8. The Board of Management shall determine in consultation with the Academic Council about examination.

9. The University may change the examination centre of the examination any time if it deems proper without assigning any reason.

10. The Controller of Examination may on the recommendation of the Centre Superintendent appoint an amanuensis to write down dictation pertaining to answers to questions during an examination on behalf of an examinee who is unable to write himself/herself if he/ she is medically handicapped and possess a certificate of a Government Medical Officer, provided that such an amanuensis shall be a man/woman possessing qualification of at least one class lower than that of the examinee concerned.

11. The' University may from time to time appoint Inspectors or Board of Inspectors to see that the examinations are conducted strictly in accordance with rules and procedures lay down. In the event of the Inspector pointing out a breach of rules or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the center, and if any such action is taken a report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.

12. The Vice-Chancellor may cancel an examination at all/ any centers' if he is satisfied that there has been leakage of question papers or any other irregularity which in his opinion warrants such a step and report the action taken at the next meeting of Board 0 f Management.

13. The Board of Management in consultation with the Academic Council may issue such general instruction for the guidance of the Examiners, Centre Superintendents, Tabulators, Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.

14. If a candidate has any communication to make on the subject of his/ her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examination directly.

15. Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his/her examination, the matter shall be reported to the Controller of Examination who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

16. Except as otherwise decided by the Board of Management, the examination answer-books and the foil and counter foil of the marks obtained by the examinees except the tabulated results, shall be destroyed 'or otherwise disposed of after 6 months from the date of the declaration of the results of the examination provided that the evaluated answer books of revaluation shall he destroyed/disposed of only after 6 months of the declaration of the revaluation result.

17. The Controller of Examination shall publish the combined results of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to the Internet. The result when published shall simultaneously be communicated to the institutions concerned.

18. The remuneration of the Examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and collators and the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as prescribed from time to time by the Board Management.

19. Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to an examiner other than the one who evaluated it initially. The examiner so appointed will check and evaluate only those questions, which have been left "unmarked. He will also check the total. The answer book will not be re-evaluated for already evaluated questions.

20. No ex-student candidate shall be admitted to an examination of the University unless he submits with his application the following

    (i) The statement of marks (in original) obtained by him as a regular candidate at the said examination issued by the University together with an attested copy thereof, or

    (ii) In case he was duly admitted to the said examination as a regular candidate but he could not appear thereat, a certificate from the institute last attended by him showing the year, the roll number and the examination to which he was admitted as a regular candidate.

21. No Candidate shall appear, in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's degree in one and the same year.

22. A candidate who has passed first year of Bachelor's degree, examination or Master's degree examination of another University/ Awarding Body (Indian or Foreign) may be admitted to the next higher examination of

    the University for the corresponding degree subject to such conditions as laid down by the Academic Council from time to time on the credit transfers.

    Provided at least 75% of the courseware offered by the University/ Awarding Body of the candidate match with the courseware of the University for the award of the corresponding degree.

23. No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

24. An application for admission to an examination received by the Controller of Examination after the last date notified by the University but not later than fifteen days after such last date may be entertained on payment of a late fee as prescribed from time to time.

25. Not withstanding anything contained in the Ordinance relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice-Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to lack or negligence on the part of the candidate and that it would be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects to be entertained with the late fee prescribed by the Board of Management from time to time even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.

26. (1) The controller of Examination shall issue an admission card in favour of a candidates if:

a) The application of the candidate is complete- in all respects.

b) The fees as prescribed have been'paid by the candidate.

c) The assignments have been submitted.

d) The attendance is more than 60%.

e) The student has scored a minimum of 50% marks in assignments and examinations collectively.

(2) Where the practical examination is held earlier than the examination

in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

(3) The admission card issued in favour of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that:

a) The admission card was issued by mistake or the candidate was not eligible to appear in the examination.

b) Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or with the application for enrolment, admission to the institute, college or school are false or incorrect.

(4) The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on the payment of a fee prescribed. Such a card shall show in a prominent place to the word "Duplicate".

27. (1) A candidate who due to sickness or other cause is unable to present himself/herself at an examination, shall not receive a refund of his fee.

Provided that the Vice-Chancellor may, in case in which he is satisfied about the genuineness or merit of it, order for adjustment of the following portion of the fee towards the next immediate examination viz.

i. Examination fee after deduction of 10% fee paid.
ii. Fee for statement of marks.

Other fees paid by the candidate shall lapse to the University. Application for such adjustment from a candidate accompanied by a Medical Certificate of illness, if applicable, must be sent so as to reach the Controller of Examination not later than 30 days from the date of commencement of the examination at which the candidate was to appear.

(2) The examination fees paid by a regular candidate who is debarred from appearing at an examination due to shortage in attendance at lectures/particals may be refunded after deduction of service charges of 10%.

(3) The examination and other fees of a candidate whose application for appearing at an examination has been rejected for some reason or he could not furnish his form within the prescribed date necessary fees having been paid in the University account, may be refunded after

deduction or service charges of 10%.

(4) The examination and marks statement fee of a candidate who dies before appearing at the examination may be refunded in full to his guardian or his successor.

(5) The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall stand forfeited.

28. (1) Any candidate, who has appeared at an examination conducted by the University, may apply to the Controller of Examination for the scrutiny of his marks in the answer scripts of theory papers in any subject and rechecking of his results. Such application must be made so as to reach the Controller of examination within 15 days of the publication of the result of the examination.

(2) Such application must be accompanied by fee as per schedule given below.

(a) In one subject Rs. 200/-

(b) In all subject Rs. 1000/-

(3) A candidate shall not be entitled to a refund of the fee.

(4) The result of scrutiny shall be communicated to the candidate.

(5) If as a result of scrutiny, if is found that the examinee should be declared as having passed or placed in a higher division, the result of the candidate shall be revised accordingly.

29. Duplicate copies of the following certificate shall be granted on payment of the fee mentioned against each viz.

(i)	Statement of Marks	Rs. 500/-
(ii)	Migration certificate	Rs. 500/-
(iii)	Provisional Certificate	Rs. 500/-
(iv)	Degree Certificate	Rs. 1500/-

Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not be granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper of proper value required by law for the time being in force that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really needs a duplicate copy. Duplicate copy shall be issued only once.

30. The names of the first ten successful candidates in each final Degree Examination other than supplementary examination who obtain first division shall be declared in order of Merit.

31. Not withstanding anything contained in the concerned ordinance an examinee who has appeared in all the theory papers, practicals, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination in 1st attempt and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the Graduate examinations but secures more than the minimum aggregate marks required, may be given a grace of upto five marks with not more than three marks given in anyone subject to enable- him to pass the examination. These marks shall, however, not be counted towards the total.

32. The Vice-Chancellor may award one grace mark in case the candidate is missing a division by one mark. Where the deficiency is so condoned one mark shall not be added to the total.

33. (1) The following shall be eligible to appear at supplementary examination.

(a) Candidates who have failed at any Bachelors/Masters examination in not more than two subjects.

(b) Candidate for examination other than those enumerated in (a) above who are declared eligible to appear at a supplementary examination in accordance with the provisions of the examination in accordance with the provisions of the respective examination Ordinance.

(2) In the case of subject for supplementary examination on which there is also a practical test, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passes in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both the parts of the subject.

(3) Except when provided otherwise in the Ordinance concerned a candidate who has been declared eligible for a supplementary examination may appear as supplementary examination candidate in the

two examinations immediately following the examination in which he was declared to be so eligible and thereafter he/she shall be required to appear in all the papers at the next examination.

(4) A candidate appearing in the supplementary examination shall be declared to have passed the examination if he secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in the examination Ordinance concerned. The marks obtained by the candidate in the supplementary/examination shall taken into account in determining the division at the examination.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2003

क्रमांक/एफ-73-187/03/उ.शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत/वेस्टर्न इंडिया यूनिवर्सिटी, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उप नियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है तथा उप नियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 26 (छब्बीस) प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

1.0 Short Title, Extent and Commencement

1.1 These Statutes shall, here-in-after be called, the FIRST STATUTES of Western India University, 2003.

1.2 These First Statutes are applicable to Western India University and any matter relating and incidental thereto.

1.3 These First Statutes shall come into force on the date of publication of these first Statutes by the Government of Chhattisgarh in the Official Gazette.

1.4 The Registered office of Western India University shall be located at Raipur.

2.0 Definitions (in alphabetical order)

In these First Statutes unless and otherwise the context demands:

a. **Academic Council** means the Academic Council of the University constituted under Section 22 of the Act and under Section 14.0 of the First Statutes.

b. **Academic Staff** means such categories of staff or employees as are designated as academic staff by the ordinances.

c. **Academic Year** ordinarily means the period from 01 April of any year to 31st March of the following year, or the dates announced by the Academic Council for a particular academic session.

d. **Act** means the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002).

e. **Ad-hoc Committee** means a committee constituted under the Section 20.0 of these First Statutes.

f. **Administrative Officer** means an officer of the University as defined under section 7.0 of the First Statutes.

g. **Affiliation** means and includes together with its grammatical variations in relation to institutions, colleges and schools, recognition of such institutions, colleges and schools by, association of such institutions, colleges and schools with, and admission of such institutions, schools, colleges to the privileges of the University; these institutions, schools and colleges may be located in or outside the state of Chhattisgarh in India and foreign countries.

h. **Authority** means authority / authorities mentioned under Section 19 of the Act and Section 10.0 of these First Statutes.

i. **Board** means the **Board of Management** of the University constituted under section 21 of the Act and section 12.0 of these First Statutes.

Board of Studies means the Board of Studies of the University for each subject or group of subjects or academic program, constituted by the Academic Council or the Vice Chancellor on its behalf.

k. **Chancellor** means the Chancellor of the University as mentioned in Section 14 of the Act and Section 4.0 of these First Statutes.

l. **Committee** means all committees constituted under Sections 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of these First Statutes.

m. **Common Seal** means the authoritative seal of the University established under Section 6 of the Act.

n. **Controller of Examination** the officer of the University created under Section 7 of these First Statutes.

o. **Courses** includes programs and courses of studies imparted in the formal mode and / or in the non – formal mode or distance education mode including web, electronic, satellite or any other means in the institutions, colleges, schools and Study Centers of or authorized by the University by whatever name these are called.

p. **Dean** means **Head of a Faculty** which may consist of one or several Programs or Institutions or Centers of Excellence / Research / Training / Consultancy, usually selected from among the Heads of such Programs / Institutions / Centers, and is the officer of the University created under Section 7 of these First Statutes.

q. **Dean (Discipline)** means the person responsible for maintaining the discipline amongst the students, faculties and staff of schools, institutions, colleges and post-graduate departments of the University, and is the officer of the University created under Section 7 of these First Statutes.

r. **Director** means **Directorate** or the officer appointed by the Management Board under Section 7 of the First Statutes for rendering general or specific or support services to the students, faculties and staff of the University and for facilitating and coordinating the functions and activities of the Deans of Faculties, Schools, Colleges, Distance Education Study Centers, Administration, and to manage the affairs of the University in the absence of the Vice–Chancellor or as delegated by him from time to time. There may be various Directors or Directorates, who will work in coordination with all concerned:

(1) **Director of Distance Education (D-EDU)** - To coordinate, execute and deliver all or some Distance Education Programs offered by the University in India and abroad.

(2) **Director of Preparatory Education (DPREP)** – To offer Preparatory Programs to all aspiring entrants, applicants, students and children who wish to join or enter into the professional and other programs offered by the University in India and abroad.

(3) **Director of Training & Placement (DTRIP)** – To network with relevant national

and international organizations and assist students of the University to seek better Training and Placement with Industry, Agriculture and Tertiary including Education, Entertainment, Service, Government and Non-Government sectors of the economy in India and abroad.

(4) **Director of Entrepreneurship Development (DENT)** – To network with relevant national and international organizations and assist students, faculties and staff of the University to develop entrepreneurship within themselves to venture into establishment of their own business in Industry, Agriculture and Tertiary sectors including own profession in Consultancy, Education, Entertainment and Service sectors of the economy in India and abroad.

(5) **Director of Women Education and Empowerment (DWEE)** – to network with relevant national and international organizations and offer programs and support towards achievement of 100% literacy and education of girls and women to enable them to become self-sufficient and sustainable in raising their children and living a respectable life.

(6) **Director of Rural Upliftment & Development (DRUDEV)** – to network with relevant national and international organizations and offer programs and support towards achievement of 100% literacy and education of rural people to enable them to become self-sufficient and sustainable in raising their standard of living and leading a respectable life.

(7) **Director of Fund Raising (D-FUND)** – To network with relevant national and international donor and funding individuals and organizations, and assist the University to secure necessary donations and funds from India and abroad.

(8) **Director of Campus Development & Security (D-CAMPUS)** – To develop, construct, maintain and generally look after all the works, cleanliness, beautification and security of the University Campus or Campuses and their faculties, schools, colleges, institutions, hostels, staff quarters / bungalows, gardens, parks, theatres and any other constituents including lands, buildings, furniture, fixtures, electrification, water, tanks, structures and other amenities.

(9) **Director of Sports, Physical Education and Recreation (D-SPORT)** – To organize and coordinate, for the benefit of students, teachers and employees, sports, athletics, physical education, medical, hygiene, recreation, festivals, expeditions, mountaineering, river rafting, air ballooning, parachuting, parasailing, flying, kite flying, go-karting, racing and other such programs, events and activities of the University and its constituents within University Campus, or in Chhattisgarh State or anywhere in India and the world.

(10) **Director of Public Relations, Entertainment and Media (D-PREM)** – To develop, manage and update website, eLearning, public relations, guest relations, publicity, printing and publishing of newsletters and magazines, advertising, entertainment, amusement and all media related programs, events

and activities of the University and its constituents within University Campus, or in Chhattisgarh State or anywhere in India and the world.

s. **Distance Education** means the education / courses / programs offered to the students in off - campus mode. It includes system of imparting education through any means of communication such as written notes and materials, broadcasting by radio, TV, Mobile devices, Satellite, Robots; classroom contact programs, Internet, email, website, e–learning or the combination of any two or more of such means.

t. **Employee** means **Staff** and includes any person appointed by the University, and includes teaching and non–teaching employees of the University who are on the payroll of the University, and it does not include any casual, temporary, contractual ad-hoc employees or visiting experts and persons who may be engaged for a specific assignment or task.

u. **Estate Manager** means the officer of the University created under Section 7 of these First Statutes.

v. **Finance Committee** means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act and Section 18.0 of these First Statues.

w. **Financial Year** means the period commencing on the 1st day of April of any year and ending with 31st day of March of the following year, or any period as prescribed by the Governing Body.

x. **Fund** means the General Fund established under Section 7 of the Act and Section 23.0 of these First Statutes.

y. **Governing Body** means the Governing Body of the University constituted under Section 20 of the Act and under Section 11.0 of the First Statutes.

z. **Government** means the Government of the State of Chhattisgarh (India).

aa. **He** includes She and His includes Her, and vice-versa.

bb. **Head** means the person by whom a Department, School, Institution or Center of Excellence / Research / Consultancy is headed, and is an officer of the University created under Section 7 of these First Statutes.

cc. **Institute** means and includes institute, institution, school and college constituted as a part of the University or affiliated by the University to impart education in specified discipline(s) located within or outside the state of Chhattisgarh, in India and Abroad.

dd. **Librarian** and **Assistant Librarian** means the officers of the University created under Section 7 of these First Statutes.

ee. **Main Campus** means the Head Quarter Campus of the University, its own and affiliated Faculties, Institutes, Colleges and Schools located at Raipur or anywhere in the State of Chhattisgarh.

ff. **Manual of Instructions** includes all provisions, procedures, instructions and systems laid down by various Committees, Boards, Authorities, and Officers of the University for the purposes of smooth functioning of the University.

gg. **Norms** means internal rules framed by the University based on its Statutes and Ordinances for facilitating its smooth operations and management.

hh. **Ordinances** mean the ordinances issued by the University as prescribed by section 27 and 28 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications to the Ordinances.

ii. **Planning Committee** means the Planning Committee of the University.

jj. **Registrar** means the officer of the University created under Section 16 of the Act and Section 6 of these First Statutes.

kk. **Deputy Registrar** and **Assistant Registrar** means the officer of the University created under Section 7 of these First Statutes.

ll. **Regulations** mean Regulations made under Section 37 of the Act.

mm. **Rules** mean the Rules made under Section 36 of the Act.

nn. **Sponsoring Body** means the Lulla Sairam Seva Society, GF-28, Millennium Plaza, Near Indian Coffee House, Raipur (Chhattisgarh) registered under the provisions of Chhattisgarh Societies Ragistrikaran Adhiniyam, and the said Society is founded by Lulla Sairam Seva Trust, 'Sai Rachana', Piramitar Road, Dandia Bazaar, Vadodara-390001 (Gujarat) for the purpose of smooth functioning and managing the affairs of Western India University, Raipur as per the Act.

oo. **Staff** means **employees** and includes any person appointed by the University, and includes teaching and non–teaching employees of the University who are on the payroll of the University, and it does not include any casual, temporary, contractual ad-hoc employees or visiting experts and persons who may be engaged for a specific assignment or task.

pp. **States means** the States of India.

qq. **Statutes** means the Statutes made under Section 25 and 26 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications to the Statutes.

rr. **Student** means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any course of study at the University, an institute of the University, Schools, Study Centers, Research Centers, Training Centers and Colleges affiliated to or approved by the University.

ss. **Study Center** means Distance Education Centers set up and/or approved by the University under the advise of the Board of Management for imparting education in formal, non-formal or distance education mode in respect of any course/s offered by the University and even in new innovative courses not offered by the University but approved by the University and located within or outside the state of Chhattisgarh in India and abroad. Such Study Centers shall be designated as University Study Centers (USC) or College Study Centers (CSC) or Village Study Centers (VSC). Such Study Centers shall function independently but within the framework of the University norms and guidelines framed from time to time. Such Study Centers for convenience may be designated as College Campus,

Ahmedabad Campus, Bangalore Campus, Chandigarh Campus, Chennai Campus, Delhi Campus, Kolkata Campus, Mumbai Campus, Hyderabad Campus, Pune Campus, Vadodara Campus, Dubai (UAE) Campus, London (UK) Campus, Washington D.C. (USA) Campus, New York (USA) Campus, New Jersey (USA) Campus, Khartoum (Sudan) Campus, Omdurman (Sudan) Campus and so on.

tt. **Teacher** means a Professor, Reader, Lecturer, Visiting Professor / Fellow, Guest Faculty or Demonstrator, and may be full-time, part-time or on visiting basis.

uu. **University** means **Western India University** established under Section 5 of **the Act** and will have the same meaning as stated in Section 2 (f) of the **University Grants Commission Act 1956** as amended from time to time.

vv. **Vice Chancellor** means the Vice–Chancellor of the University appointed within the meaning of section 15 of the Act and Section 6.0 of these First Statues.

ww. **Visitor** means the Visitor of the University as defined under Section 13 of the Act.

3.0 Objects of the University

The Objects of the University are listed below:

3.1 To provide instructions, teaching and training in Higher Education and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge;

3.2 To create higher levels of intellectual abilities from ordinary persons;

3.3 To establish state of the art facilities for education and training in Chhattisgarh, Gujarat, Union Territories of Daman & Diu, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, Chandigarh, as well as other States or parts of India and the world;

3.4 To carry out teaching and research and offer distance education and continuing education programmes;

3.5 To create centers of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application in all areas including education, industry, agriculture, business, trade, commerce, export-import, banking, insurance, services, management, science & technology, space and other areas of future, and institute awards and fellowships for undertaking research at University as well as at other Institutions / Centers of the University in India and Abroad;

3.6 To provide consultancy to the industry, education, eTrade /eBusiness, amusement, agriculture and public organizations;

3.7 To establish main campus in Chhattisgarh and to have affiliated colleges and approved study centers at different places in India and other countries;

3.8 To establish examination centers;

3.9 To institute degrees up to doctoral and post-doctoral levels, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination, selection, or any other method of evaluation including work experience, research, dissertation, self certification, online evaluation, outstanding contribution to the body of knowledge, academia or society, but not limited to these, as laid down by the Academic Council;

3.10 To withdraw degrees, diplomas, Certificates and other academic distinctions for good and sufficient cause or causes as recommended by the Academic Council.

3.11 To affiliate, recognize or collaborate with any other college, University, research institution, industry and trade association, professional association, industrial unit, business, Government or any other organization in India or abroad to conceptualize, design and develop specific educational and research programs, training programs, exchange programs and such other programmes which the University may consider appropriate for students, faculty members, scientists, staff and others.

3.12 To undertake programs for the training and development of faculty members of the University from other institutions in India or aboard.

3.13 To undertake collaborative research with any organization in India or abroad, and undertake commercialization of technologies.

3.14 To develop, register and license all forms of Intellectual property rights including trademarks, copyrights, know–how and patents, etc.

3.15 To conceptualize, design, develop and commercialize various products, equipments and machinery as part of the research and development activity.

3.16 To confer Honorary Degrees and other academic distinctions in the manner laid down in the statues and ordinances.

3.17 To encourage sports, cultural, extra curricular and co - curricular activities for the students and the staff.

3.18 To do all things necessary to promote the above objectives.

3.19 To pursue any other objective as may be approved by the Governing Body but within the framework of the University Act.

3.20 To pursue any other objective as may be approved by the State Government from time to time;

3.21 To ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by AICTE / NCTE / UGC / MCI / CCH, Pharmacy Council and any other Central and/or State Government Body.

4.0 Appointment, Powers and Responsibilities of the Chancellor

4.1 The Sponsoring Body with the prior approval of the Visitor shall appoint the Chancellor.

4.2 The term of office of the Chancellor shall be three years.

4.3 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and the head of the University.

4.4 The Chancellor shall preside over the Convocation of the University, when the Visitor is not present.

4.5 The Chancellor shall have the following powers.

4.5.1 To call for any information on record.

4.5.2 To appoint the Vice–Chancellor.

4.5.3 To remove the Vice-Chancellor.

4.5.4 To exercise such other powers as may be delegated to him by the Governing Body.

4.6 The Chancellor shall be responsible for excellent governance of the University and shall work as its ambassador in India and abroad.

4.7 The Chancellor may delegate any of his powers to the Vice-Chancellor as he may deem fit in the best interest of the University.

4.8 The Chancellor shall have such qualifications and experience and draw such emoluments as may be prescribed by the Governing Body from time to time.

4.9 If in the opinion of the Sponsoring Body, the actions of the Chancellor are in any way detrimental to the interests of the University, it may with prior approval of the Visitor, recall and replace the Chancellor. The sponsoring Body shall appoint such other person as may be found appropriate for the position of Chancellor to succeed the person, with the prior approval of the Visitor.

5.0 Appointment, Powers, Duties and Responsibilities of the Vice-Chancellor

5.1 The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body.

5.2 The terms of the office of the Vice-Chancellor shall initially be for a period of four years. The Chancellor may reappoint him for another term not exceeding four years.

5.3 The Vice-Chancellor shall be the principal academic officer of the University and also be the ex-officio member of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and such other Committees that may be set up by the Governing Body or the Board of Management from time to time.

5.4 The Vice-Chancellor shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the various authorities of the University, and shall exercise such power and perform such duties as may be prescribed by the Act, the Statues and Ordinances from time to time.

5.5 In the absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall undertake all the functions of the Chancellor. He shall preside over the Convocation in the absence of the Visitor and the Chancellor.

5.6 If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary in consultation with the Chancellor and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority, who would have in the ordinary course dealt with the matter. Provided that if in the opinion of the concerned authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision there on shall be final. Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is

communicated to him, an appeal to the Governing Body and the Governing Body may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice–Chancellor.

5.7 If in the opinion of the Vice–Chancellor any decision of any authority of the University is outside the power conferred by the Act, Statutes or Ordinances and the same is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor, and his decision thereon shall be final.

5.8 If at any time upon representation being made or otherwise, and after making such enquiries as may be deemed necessary, the Chancellor on the recommendations of the Governing Body may by an order in writing with or without stating the reasons therein, ask the Vice Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

5.9 The Vice-Chancellor may constitute such committees, as he deems necessary to help him in the discharge of his duties entrusted to him by or under the Act.

5.10 The Vice-Chancellor may sanction an allowance to an employee of the University for any special duties assigned to such an employee or additional duties performed by him, which in the opinion of the Vice- Chancellor warrants such payments. Provided that such allowance shall not exceed thirty percent of the basic salary of such employee.

5.11 The Vice-Chancellor may sanction such posts, as he deems necessary to help him in the discharge of his duties.

5.12 The Vice-Chancellor shall have such qualifications and experience and draw such emoluments as may be prescribed by the Governing Body from time to time.

6.0 Appointment, Powers, Duties and Responsibilities of the Registrar

6.1 The Registrar shall be appointed by the Vice–Chancellor, based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose, with the approval of the Chancellor.

6.2 The Selection committee shall consist of the following members.

i. One representative of the Vice-Chancellor.

ii. One representative of the Sponsoring Body, who is also a member of the Governing Body.

iii. One expert nominated by the Sponsoring Body, who is not in any way connected with the University,

6.3 The term of office of the Registrar shall not exceed 3 years.

6.4 The Registrar shall have such qualifications and experience and draw such emoluments as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

6.5 The Registrar shall undertake all such functions and responsibilities as may be specified by the Governing Body, the Board of Management and the Vice-Chancellor.

6.6 The Registrar shall be the ex-officio non-member Secretary of the Board of

Management and ex-officio Secretary of the Academic Council and sucn other authorities and bodies as may be constituted by or under the Act, the Statutes and the Ordinances as recommended by the Board of Management.

6.7 The Registrar shall report to the Vice-Chancellor or the Chancellor in absence of the Vice-Chancellor.

6.8 The following shall be the duties of the Registrar:

(i) To be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Governing body or the Board shall commit to his charge.

(ii) To exchange the official correspondence on behalf of the authorities of the University.

(iii) To make Agenda and issue Notices of meetings of the authorities of the University and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities with the approval of the Vice-Chancellor.

(iv) To keep the minutes of the meetings of all the authorities and sub committees appointed by any of these authorities and circulate the same among the members, with the approval of the Vice- Chancellor.

(v) To sign contracts and documents and authenticate records on behalf of the University.

(vi) To submit information, reports and documents to the Government and liaise with the State Government, Central Government, University Grants Commission and other Government authorities.

(vii) To generally supervise the administrative functions of the University.

7.0 Appointment, Powers, Duties and Responsibilities of Other Officers

7.1 The following shall be the other Officers of the University:

7.1.1 Administrative Officer

7.1.2 Assistant Librarian

7.1.3 Assistant Registrar

7.1.4 Controller of Examination

7.1.5 Dean

7.1.6 Deputy Registrar

7.1.7 Director (as defined in Section 2 of the First Statutes)

7.1.8 Director of Distance Education (D-EDU)

7.1.9 Director of Sports, Physical Education and Recreation (D-SPORT)

7.1.10 Estate Manager

7.1.11 Finance / Accounts Officer

7.1.12 Head

7.1.13 Librarian

7.2 The qualifications of the Officers shall be as per the norms of UGC / AICTE / MCI / HCI / any other Regulatory Council or Agency as applicable.

7.3 The pay scale shall be generally at par with the UGC Norms and approved by the Board of Management and the State Government where applicable. However, the Board of Management of the University shall be empowered to change the pay of officers considering their qualifications and experience.

7.4 **Deputy Registrar** may be given the charge of **Controller of Examination**.

7.5 The **Controller of Examination** shall report to the Vice-Chancellor.

7.6 The following shall be the duties of the Controller of Examination for which he shall be fully responsible:

7.6.1 Timely and smooth conduct of the combined entrance test and the semester-end or year-end examinations.

7.6.2 Laying down the guidelines for the setting up of the examination papers.

7.6.3 Appointing internal as well as external examiners through the examination committee for each subject and get at least 2 sets of question papers prepared well in advance.

7.6.4 Appointing a moderation committee and getting all papers moderated before these are sent for printing or email or web access

7.6.5 Ensuring timely dispatch of answer books and Admit Cards to all examination centers.

7.6.6 Getting the answer books evaluated in accordance with the guidelines laid down by the paper setter.

7.6.7 Getting the results compiled accurately and declared in time.

7.6.8 Re-evaluation of the answer books in prescribed time limit on request from the students for a fee as prescribed by the Board of Management.

8.0 Appointment, Qualifications, Terms and Conditions of Teachers

8.1 There shall be following categories of Teachers.

8.1.1 Professor, Associate Professor, Assistant Professor

8.1.2 Reader

8.1.3 Lecturer

8.1.4 Visiting Professor / Fellow

8.1.5 Guest Faculty

8.1.6 Demonstrator.

8.2 The qualifications and experience of the Teachers shall be as per the norms of the UGC / AICTE / MCI / HCI / any Regulatory Council or Agency as applicable.

8.3 The Pay Scales shall be generally at par with the UGC Norms and approved by the

Board of Management and the State Government where applicable. However, the Board of Management of the University shall be empowered to change the pay of Teachers considering their qualifications and experience.

8.4 The Board shall formulate the terms and conditions of appointment and service conditions of the teachers, faculty members, officers and employees.

8.5 The registrar shall issue the appointment letters to the teachers, faculty members, officers and employees in accordance with the policies and procedures as formulated by the Board.

9.0 Appointment, Powers, Duties and Responsibilities of Chief Finance & Accounts Officer

9.1 The Chief Finance & Accounts Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose.

9.2 The selection committee shall consist of:

9.2.1 One representative of the Vice-Chancellor.

9.2.2 One representative of the Sponsoring Body, who is also a member of the Governing Body.

9.2.3 One expert nominated by the Sponsoring Body, who is not in any way connected with the University.

9.3 The Chief Finance & Accounts Officer shall have such qualifications and experience as the Board of Management may prescribe from time to time.

9.4 The Chief Finance & Accounts Officer shall draw such salary, allowances and be entitled to such perquisites, which shall be fixed by the Board of Management from time to time.

9.5 The term of office and the terms of appointment of the Chief Finance & Accounts Officer shall be as mentioned in his order of appointment by the Vice-Chancellor.

9.6 The Vice-Chancellor may appoint Finance & Accounts Officer who will assist the functioning of the Chief Finance and Accounts Officer and act in his absence to discharge day-to-day duties and responsibilities. The Finance & Accounts Officer shall report to the Chief Finance & Accounts Officer or the Vice-Chancellor in the absence of the former.

9.7 The Chief Finance & Accounts Officer shall exercise general supervision over the funds of the University and shall have such powers and responsibilities as may be delegated or assigned to him by the Board of Management as per the recommendations of the Finance Committee.

9.8 The Chief Finance & Accounts Officer shall report to the Vice-Chancellor or Registrar in absence of the Vice-Chancellor.

10.0 Authorities of the University

10.1 The Governing Body

10.2 The Board of Management

10.3 The Academic Council

10.3.1 The Board of Studies (for each Program / Subject)

10.4 The Finance Committee

10.5 The Examination Committee

10.6 Other or Ad-hoc Committees

The powers and functions of the above authorities shall be as follows:

11.0 The Governing Body

The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

11.1 Constitution of the Governing Body

1. The Chancellor
2. The Vice-Chancellor
3. Three persons nominated by the Sponsoring Body.
4. One representative of the State Government
5. One educationist of repute to be nominated by the Government.
6. One academician to be nominated by the Visitor.

11.1.1 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body.

11.2 Term of the Governing Body

The members of the Governing Body shall have a term of 4 years.

11.3 Disqualifications of the Members of the Governing Body

The members of Governing Body shall cease to be the members under the following circumstances:

11.3.1 If the member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

11.3.2 If the act and conduct of a member is detrimental to the interest of the University, the Sponsoring Body shall have the powers to replace or recall such member in consultation with the nominating authority.

11.4 Powers and Functions of the Governing Body

11.4.1 The Governing Body shall have the following powers.

i To make arrangement for managing the affairs of the University in the absence of the Vice-Chancellor.

ii. To appoint Auditors of the University.

iii. To oversee the performance and review the important decisions of other authorities of the University, whether these are in

conformity with the Act, Rules, Statutes or Ordinances or not.

iv. To approve the Annual Report and Accounts of the University.

v. To lay down the vision, mission, objectives, goals, policies and strategies of the University.

vi. To take decision about the voluntary Liquidation of the University.

vii. To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University.

11.4.2 The Governing Body shall perform such other functions and have such other powers as are not otherwise provided for and are necessary for proper functioning, administration and management of the University and its academic affairs.

11.4.3 The Governing Body has the power to recall and replace any officer or authority of the University if it deems fit in the best interest of the University. It shall do so in consultation with the nominating authority and till such time a replacement is obtained, it will delegate the power of that authority / officer to any other authority / officer or to itself as it may deem fit.

11.5. Reserve Powers of Governing Body

11.5.1 In Case of any deadlock in the functioning of the Board of Management and if in the opinion of the Governing Body the affairs of the University cannot be transacted in the normal course, the Governing Body shall have the powers to do all the necessary things including superceding the existing Board of Management and forming a new Board of Management to facilitate smooth functioning of the University.

11.5.2 The Governing Body may also exercise the reserve powers suo-moto or as and when a written report is submitted by any officer or authority of the University to the Chancellor or the Vice-Chancellor about the deadlock in the functioning of the Board of Management.

11.5.3 Upon receipt of such a report the Chancellor or the Vice–Chancellor shall convene a special meeting of the Board of Management within 15 working days for restoration of normalcy of operations.

11.5.4 The decisions taken by the Governing Body and implemented by the officers under this clause shall be final and binding on all members of the Board of Management and on all the Members of the Governing Body.

11.6 Meeting of the Governing Body

11.6.1 The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year on any working day, at the headquarters of the University or any other locations in

India or abroad as agreed to by majority of the members.

11.6.2 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body. In the absence of the Chancellor, the President or the Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

11.6.3 A notice of 7 days shall be given to the members stating the agenda for the meeting.

11.6.4 The quorum of the meeting shall be 5 members present in person.

11.6.5 Each member of the Governing Body including the presiding officer shall have one vote and simple majority shall adopt decisions at the meeting.

11.6.6 The presiding officer of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of 15 days from the date of such a meeting.

11.7 Extraordinary meeting of the Governing Body

11.7.1 In the event of exigency, the Chancellor or the Vice-Chancellor may call for an extraordinary meeting of the Governing Body.

11.7.2 The Sponsoring Body may, in the event of exigency and / or in the interest of the administration and management of University, in consultation with the Chancellor or the Vice Chancellor, call for an extraordinary meeting of the Governing Body by circulating a resolution amongst the members. But in that meeting by circulation, no policy or financial matter shall be taken in to consideration.

11.7.3 The Chancellor or the Vice-Chancellor may under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members and any such resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing Body.

12.0 The Board of Management

The Board of Management shall be the principal executive body of the University.

12.1 Constitution of the Board of Management

12.1.1 Following members shall constitute the Board of Management:

i. The Vice-Chancellor (ex-officio) - Chairman

ii. Two nominees of the Sponsoring Body

iii. One representative to be nominated by the State Government.

iv. Senior most Professor of the University to be nominated by the Vice-Chancellor.

12.1.2 The Vice-Chancellor shall be Chairman of the Board and the Registrar shall be the non-member Secretary.

12.1.3 The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Board and in the absence of the Vice-Chancellor; the members present in the meeting may select

one of them as the Chairperson of the meeting.

12.1.4 The tenure of the members of the Board of Management shall be three years, except in the case of ex-officio members which will be as per their terms of appointment.

12.2 Disqualifications of the Members of the Board of Management

The members of the Board of Management shall cease to be the members under the following circumstances:

12.2.1 If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

12.2.2 If in the opinion of the Chancellor, a member of the Board acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, in consultation with the nominating authority ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

12.3 Meetings of the Board of Management

12.3.1 The Board of Management shall meet as often as necessary, and at least once in three calendar months at the headquarters of the University or any other locations in India or abroad as agreed to by majority of the members.

12.3.2 The Registrar shall convene the meetings.

12.3.3 A notice of 7 days shall be given for the meeting, provided that an emergency meeting may be convened at the discretion of the Vice- Chancellor at a short notice of not less than 3 days.

12.3.4 The quorum of the meetings shall be 3 members present in person.

12.3.5 Each member of the Board including the Chairman / Presiding officer shall have one vote and simple majority shall take decisions at the meeting. In case of a tie, presiding officer shall exercise a casting vote.

12.3.6 The registrar shall cause recording of minutes of the meeting, with the approval of the Vice–Chancellor and circulate them to the members concerned within a period of 15 days from the date of conduction of the meeting.

12.3.7 The Vice–Chancellor may under exigencies, obtain the consent of the Board by circulating appropriate resolution among its members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board. The Vice-Chancellor shall put such passed resolution before the Board of Management in its regular next meeting. In case the Board of Management in its regular meeting disapproves the resolution, then the matter shall be referred to the Chancellor and his decision shall be final.

12.4 Powers and Functions of Board of Management

The Board of Management shall have the power to take all the necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University. The powers shall, interalia, include but not be limited to the following:

12.4.1 Staffing

12.4.1.1 To manage and administer all revenues and properties of the University and to conduct all administrative affairs of the University not otherwise specifically provided for.

12.4.1.2 To create teaching, academic, administrative, ministerial and other necessary posts and to decide on the number, qualifications and cadre thereof, and to determine the emoluments for such posts in consultation with the Finance committee.

12.4.1.3 To appoint Directorates, Directors, Associate Directors, Principals, Vice Principals, Deans, Associate Deans, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Readers, Senior Lectures, Lectures, Junior Lectures, Research Fellows, Research Associates, Research Assistants, Teachers, Teaching Assistants, operational and support staff, administrative, ministerial and other staff as may be necessary on recommendations of the duly constituted selection committee.

12.4.1.4 To lay down the terms, conditions and norms in respect of emoluments, duties and responsibilities of the various academic and non-academic staff recruited by the University by the regulations.

12.4.1.5 To lay down the provisions for appointment of Visiting Fellows, Visiting Professors, Professors Emeritus, Consultants, Advisors, Scholars and such special positions and determine the terms and conditions of such appointments.

12.4.1.6 To appoint internal auditors to undertake concurrent audit of the various functions of the University.

12.4.2 Academic Matters

12.4.2.1 To generally lay down in consultation with the Academic Council, the academic policies, education, teaching, training, consulting and research standards and policies relating to students admission, examinations and award of degrees, diplomas, certificates and other academic awards or distinctions.

12.4.2.2 To create, establish, set up, affiliate existing and new, based on the advice of the Academic Council, Faculties, Schools, Colleges, Institutes, University Study Centers, College Study Centers specific to one discipline or multiple / cross-functional disciplines of Higher Education and to allocate

areas of Learning, Study, Teaching, Training, Placement, Research, Consultancy, Extension, Welfare and other services to them on terms and conditions and for such tenure as approved by itself from time to time.

12.4.2.3 To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the Regulations and Ordinances.

12.4.2.4 To lay down provisions regarding the emoluments and traveling and other allowances of examiners appointed for examination, tabulation and such other personnel appointed for conduction of examination, in consultation with the Academic Council and the Finance Committee.

12.4.2.5 To acquire intellectual property rights, copyrights, trademarks, logos, goodwill, networks and the likes from any institution or organization, on such terms and conditions as the Board may determine, and pay such compensation for the acquisition as may be just and equitable.

12.4.3 Finance

12.4.3.1 To consider the budget as recommended by the Finance Committee and to approve the same with or without modifications.

12.4.3.2 To raise funds, receive donations, endowments, fees and other charges, royalties, consultancy and other income, and to manage, administer and utilize such funds and revenues, to regulate the finance, accounts, investments, property and all other administrative, management, marketing and human resource development affairs of the University, and for that purpose appoint such consultants, advisors, experts and agent(s) from India or abroad on such terms and conditions as it may deem fit, and to pay out of the funds of the University, all fees and expenses, incidental to raising of such funds, donations and endowments.

12.4.3.3 To open account(s) of the University with any one or more scheduled banks and to lay down the procedure for operating the same.

12.4.3.4 To draw, accept, make, endorse, discount and negotiate securities of the Government promissory notes, Bills of exchange, cheques or other negotiable instruments.

12.4.3.5 To receive and give grants, donations, contributions, gifts, prizes, scholarship, fees and other moneys.

12.4.3.6 To purchase, take on lease, accept as gift or otherwise any land or buildings or work which may be required for the purposes of the University on such terms and conditions as deemed appropriate and to construct or alter and maintain any such buildings or works.

12.4.3.7 To transfer or accept transfers of any moveable property on behalf of the University.

12.4.3.8 To advice the Sponsoring Body on matters regarding acquisition, management and disposal of any movable and immovable property on behalf

of the University.

12.4.3.9 To execute in consultation with the Sponsoring Body, conveyance, transfer, re-conveyances, mortgages, leases, bonds, licenses, and agreements in respect of property, moveable or immovable, belonging to the University or to be acquired for the purposes of the University.

12.4.3.10 To provide building(s) premises, furniture, fittings, equipments, appliances, automobiles, vehicles, airplanes, boats, machinery and other facilities required for smooth functioning of the University and its constituted faculties, schools, colleges, research centers, centers of excellence, training centers, study centers, regional / state / country / national offices, guest houses etc.

as well as housing, roads, playgrounds, theatres, shopping centers, health centers / clinics, hospitals, recreational, entertainment and amusement amenities for academic and non-academic staff, and cause their maintenance, depending upon financial health of the University.

12.4.3.11 To appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit.

12.4.3.12 To invest the funds of the University or money entrusted to the University, in such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time swap an investment in the best interest of the University.

12.4.3.13 To raise and borrow money, loans, notes or other obligations or securities in consultation with the Sponsoring Body by providing properties and assets of the University as securities, or borrow money without any securities, and upon such terms and conditions as it may think fit, and to pay out of the funds of the University, all fees and expenses, incidental to raising of money and to repay and redeem any money borrowed with or without interest as applicable.

12.4.3.14 To establish maintain and operate the General Fund as stipulated in Section 7 and 8 of the Act and Section 23.0 of the First Statues.

12.4.3.15 To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts including the Balance Sheet for every previous financial year, in such from as may be prescribed by the Regulations and submit the same to the Governing Body for their approval.

12.4.3.16 To fix limits of the total non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee.

12.4.3.17 **Ownership of revenue generating activities:** All innovations, discoveries, patents, commercially viable concepts and products shall be the property of the University assuming that these advancements were made using the resources, facilities and sponsorship of the University and/or its affiliated colleges, institutions, research centers, centers of excellence, training

centers, study centers, units or personnel.

12.4.3.18 **Individual Intellectual property matters:** The Finance Committee may recommend and the Board of Management will decide the matters related to individual intellectual property ownership on case by case basis. The University will retain all rights to all patents, commercial and other revenues. The Board of Management will review each case and give its decision based on which the University may enter into separate arrangements with individuals related to intellectual property matters.

12.4.3.19 **Conflict resolution:** All conflicts pertaining to items above will be resolved by the Board of Management using appropriate internal committee, and its decision so taken shall be final and binding to all concerned.

12.4.4 Student Affairs

12.4.4.1 To regulate and enforce discipline among the students of the University and to take appropriate disciplinary action wherever necessary.

12.4.4.2 To entertain and adjudicate upon appeals and grievance of the students of the University through the Committees setup for the purpose.

12.4.4.3 To establish and regulate the maintenance of hostels for the students for the University and recognize hostels established by outside parties on the basis of the recommendations of a committee established for the purpose.

12.4.5 Administrative and Legal Matters

12.4.5.1 To enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and to do all such acts as are necessary to raise resources for furthering the objectives of the University.

12.4.5.2 To grant leave of absence to any officer of the University other than Chancellor and Vice-Chancellor and to make necessary arrangements for discharge of the functions of such officers during their absence.

12.4.5.3 To regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take appropriate disciplinary actions whenever necessary.

12.4.5.4 To entertain, adjudicate upon and if considered fit, to redress any grievance of the employees of the University, who may for any reason feel aggrieved.

12.4.5.5 To select an emblem and to have a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal.

12.4.5.6 To conduct inspections and enquires in various departments, colleges, study centers, research centers, centers of excellence, institutions and affiliated colleges of the University and initiate corrective actions whenever and wherever needed.

12.4.6 Formation of Committees

The Board of Management may form such committees for such purposes and with such powers as the Board may deem fit and co-opt such persons on these committees as it may think fit.

13.0 Delegation of Powers

The Governing Body and the Board of Management may by a resolution, delegate to the President, Vice-Chancellor, Registrar, Chief Finance & Accounts Officer, Finance & Accounts Officer, Standing Committee or the Ad-hoc Committee, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-Chancellor or the Standing Committee or the Ad-hoc Committee, or any of their Officers to whom such powers are delegated, shall be reported at the next meeting of the Governing Body and the Board of the Management as applicable.

14.0 The Academic Council

The Academic Council shall be principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of the Act, the statutes, the Ordinances and the Regulations, coordinate and exercise general control and supervision over the academic policies, strategies, programs and affairs of the University and be responsible for the maintenance of standards of education, teaching, training, research, consulting, tests, examination, interdepartmental co-ordination within the University, and proper interface with the outside world for above purposes.

14.1 Constitution of the Academic Council

14.1.1 The Academic Council Shall consists of the following members.

- i. The Vice-Chancellor (ex-officio) – Chairman
- ii. The Registrar – Non-member Secretary
- iii. Director, Dean, Heads of Various Schools, Colleges, Directorates, Research Centers, Centers of Excellence, Training Centers of the University.
- iv. Three faculty members to be nominated by the Vice-Chancellor.
- v. Three outside experts nominated by the Vice-Chancellor.

14.1.2 The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

14.1.3 The term of the members of the Academic Council other then the Ex-officio members shall be two years. However, in the case of the employees of the University, the term shall end immediately after their relinquishing their office at the University.

14.1.4 Subject to the provisions of the Act, Statutes, Ordinance and the Regulations, the Academic Council shall have the power to control, regulate and maintain the standards of education, instruction and examination of the University and shall

exercise such other powers and functions as may be conferred upon it by this Act, Statutes or the Ordinances.

14.1.5 The Vice Chancellor may invite such other persons as he may deem fit to attend the meetings of the Academic Council from time to time. However, the invitees shall not be eligible to vote on any of the resolutions of the Academic Council.

14.2. Disqualification of the Members of the Academic Council

14.2.1 Where as a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

14.2.2 A member of the Academic Council shall cease to be a member in the Following circumstances also.

i. If the member resigns from the Academic Council.

ii. If the member becomes mentally unsound.

iii. If the member had been convicted of a criminal offence Involving moral turpitude or any other reason, and a higher court has not stayed such conviction.

iv. If the member fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without leave of the Chairman.

14.3 Meetings of the Academic Council

14.3.1. The Academic Council shall meet as often as may be necessary at the headquarters of the University or any other locations in India or abroad.

14.3.2. One third of the total members of the Academic Council shall constitute the quorum of the meeting of the Academic Council.

14.3.3. Resolutions of the Academic Council may be passed through circulation among all the members, except in cases where such Resolutions are required to be passed at a meeting. The resolutions so circulated and approved by a simple majority shall be effective and bindings as if such Resolutions had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the Resolution.

14.4. Functions and Powers of the Academic Council

Subject to the provisions of the Act, Statues and the Ordinance, the power of the Academic Council shall include, interalia, the following.

14.4.1 To exercise general supervision over the academic work of the University and to give direction regarding academic innovations, new areas of academic disciplines, methods of learning, teaching and instructions, evaluation, research, consultancy, extension and constant improvement in the academic standards.

14.4.2 To report and act on any matter referred to or delegated to it by the Board of Management.

14.4.3 To formulate different courses and programs to be imparted to the students, teachers and staff of the University, and various segments of economy like industry, agriculture, tertiary and services sectors in Chhattisgarh, India and abroad by all means of teaching, learning and communication.

14.4.4 To lay down the curriculum and to frame and/or approve syllabus for any of the courses and programs offered by the University, and publish textbooks, eBooks, eNotes, study materials, notebooks, presentations and other instruction and practice materials for the same.

14.4.5 To innovate, constantly upgrade and improve the syllabus of courses and programs to include emerging and futuristic faculties, disciplines, technologies, techniques and systems.

14.4.6 To make recommendations to the Board of Management, with regard to creation, abolition and classification of teaching positions or posts in the University and the emoluments and the duties and responsibilities attached thereto.

14.4.7 To formulate and modify or revise schemes for the creation and organization of the faculties, colleges and schools, and to assign to such faculties, schools and colleges their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the creation, abolition or division, combination or collaboration among faculties, colleges and schools in offering academic and training programs, teaching, research, consultancy and extension services.

14.4.8 To make regulations for lateral entry of students from other Universities / Boards of Technical Education of Indian or Foreign Origin.

14.4.9 To promote research, consultancy, training and extension activities and programs, and to ask for, from time to time, reports on such activities and programs from faculties, colleges, schools, study centers, training centers, research centers, centers of excellence etc.

14.4.10 To consider proposals submitted by the faculties, schools and colleges relating to instructions, teaching facilities, etc;

14.4.11 To appoint committees for admission of students to the University courses and programs.

14.4.12 To recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions located in India and Abroad and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University on reciprocal basis in consultation with Association of Indian Universities (AIU) or any other relevant association or authority from time to time.

14.4.13 To make regulations for awarding admission to Under-Graduate (UG) and Post-Graduate (PG) programmes of the University to such candidates from India or abroad, who do not posses formal University / Technical Education Board /

Secondary Board of Education / School Education Board qualification otherwise mandatory for admission to such courses, but have the knowledge, skills and competencies in the specific and related discipline which are capable of quantification or evaluation for the purpose of establishing equivalence with such programs.

14.4.14 To approve conferment of degrees up to doctoral and post-doctoral levels, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honour on the basis of the results declared.

14.4.15 To make guidelines for the award of fellowships, stipends, scholarships, medals and prizes, etc. and empower the vice Chancellor or any other officer of the University to approve the eligible candidates for such awards.

14.4.16 To prepare such forms and registers as are from time to time, prescribed by regulation and to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts, as may be necessary, for the purpose of the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and / or the regulations.

14.4.17 To make recommendations to the Board of Management on:

i. Measures for improving standard of teaching, examinations, training, research, consultancy, and extension services.

ii. Institution of honorary degrees of doctoral and post-doctoral levels to the outstanding personalities from India and abroad.

iii. Institution of Fellowships, Exchange Programs, Scholarships, Medals, Prizes, Titles etc.

iv. Provisions or norms covering the academic functioning of the faculties, colleges and schools, study centers, research centers, training centers, centers of excellence, discipline, residence, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, behaviour etc. and submit the same to the Board of Management for approval.

14.4.18 To suggest measures for inter-departmental and inter-disciplinary coordination.

14.4.19 To appoint committees consisting of such members as the Academic Council may deem fit to deal with any of the matters ordinarily dealt with by the Academic Council.

14.4.20 To approve new courses and programs not being offered by the University or other institutions like AICTE, UGC etc.

14.5 The Board of Studies

14.5.1 The Board of Studies shall be constituted for each Program / Subject to devise and recommend subjects and syllabus, to prepare study materials etc.

14.5.2 The Vice-Chancellor shall constitute various Boards of Studies as and when required.

14.5.3 A Board of Studies may submit its Report to the Vice-Chancellor within 30 days of its appointment. Otherwise, the Vice-Chancellor may appoint another Board of Studies to carry out the same or different functions.

14.5.4 The remuneration / honorarium to be paid to the members of Board of Studies shall be devised by the Vice-Chancellor from time to time in consultation with the Academic Council and approved in a meeting of the same.

14.5.5 The Vice-Chancellor at its discretion may follow the recommendations / Reports of the Board of Studies.

15.0 The Boards of Advisors

15.1 The Governing Body may by a resolution constitute a **Global Advisors Board**. The Global Advisors Board will render advice to the Governing Body and to the Board of Management in new areas of academics, research, consulting, training and extension services, fund raising as well as enhancing the academic and management standards. The members of the Global Advisors Board shall consist of eminent scientists, educationists, industrialists, agriculturists, consultants, service providers and personalities drawn from India and abroad.

15.2 The Board of Management may by a resolution constitute a **Board of Advisors.** The Board of Advisors will render advice to the Governing Body as also the Board of Management in managing the affairs of the University and enhancing its academic standards. The members of the Board of Advisors shall consist of eminent academicians, educationists and experts drawn from the governing councils and academic councils of the faculties, schools, colleges, institutes, research centers, training centers, centers of excellences of the University.

16.0 Examination Committee

16.1 The Vice-Chancellor shall constitute Examination Committee for the purpose of recommending suitable persons for appointment as examiners for various examinations and for suggesting evaluation methods for each subject.

16.2 The examination Committee shall consist of:

i. The Vice- Chancellor – Chairman

ii. Controller of Examination - Member Secretary

iii. Two Teachers from the faculty / college / school / institute of the University

iv. Two experts nominated by the Vice-Chancellor.

16.3 The examination committee shall recommend a Panel of Examiners for each subject of the course(s) of study to the Vice-Chancellor.

16.4 The Vice-Chancellor shall ordinarily appoint examiners from the panel recommended by the examination committee, or he may appoint examiners from outside the panel, if he deems it fit and necessary.

17.0 Result Committee

17.1 The Vice-Chancellor shall constitute Result Committee to approve the results of various examinations before they are declared.

17.2 The Result Committee shall consist of:

i. Vice-Chancellor – Chairman

ii. Dean(s) of faculty / college / school / institute of the University.

iii. One expert nominated by the Chancellor.

iv. The Registrar.

v. The Controller of Examination - Member Secretary.

18.0 The Finance Committee and its constitution

The Governing Body shall appoint the Finance committee.

The Finance Committee shall consist of the following members:

i. The Vice-Chancellor.

ii. The Chief Finance and Accounts Officer - Member Secretary.

iii. Three nominees of the Sponsoring Body.

iv. The Registrar.

The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Committee and in his absence; the members present shall elect one of them as the Chairman of the meeting.

18.1 Meetings of the Finance Committee

18.1.1 The committee shall meet as often as necessary at the head quarter of the University or any other locations in India or abroad.

18.1.2 Three members of the committee shall constitute the quorum.

18.1.3. The Chief Finance Officer shall call the meeting of the Finance Committee with the approval of the President or the Vice-Chancellor.

18.1.4. A notice of 7 days shall be given to its members stating the agenda, time and place of the meeting, provided that an emergency meeting can be called by the Vice-Chancellor at a shorter notice.

18.1.5. The Chief Finance and Accounts Officer shall cause recording of the minutes and resolutions of the meeting and circulate the same with the approval of the Vice-Chancellor within 15 days of such meeting.

18.2 Powers and Functions of the Finance Committee

18.2.1 To make recommendation on all financial matters to the Board.

18.2.2 To consider all proposals for capital expenditure and to make recommendations to the Board.

18.2.3 To examine the annual accounts of the University and advice the Board

18.2.4 To examine the annual budget estimate and advise the Board.

18.2.5 To review the financial position of the University periodically and recommend to the Board any action to be taken.

18.2.6 To keep a constant watch on the state of cash and bank balances and on the state of investments.

18.2.7 To ensure that the limit fixed by the Governing Body and the Board of Management for recurring and non-recurring expenditure for a period or an year are not exceeded and that all moneys are spent or saved for the purpose/s for which they have been granted / allotted / budgeted, or such saved moneys are returned to the General Fund of the University for other uses.

18.2.8 To review the internal controls and act on the comments of the internal auditors.

18.2.9 To make recommendations to the Board of Management on all proposals involving raising of funds, donations, endowments, loans, receipts and expenditure.

18.2.10 To determine and fix the fees payable by the students of the University and lay down the procedure thereof.

18.2.11 To fix the basis for charging and/or sharing consultancy and other fees and royalties to be charged by the University and / or any of its faculties, schools, colleges, study centers, research centers, training centers, centers of excellences of the University for rendering its services through its professors, faculty members and teachers, in the light of use of its infrastructure, properties, body of knowledge, materials, intellectual properties and the name.

18.2.12 To generally perform and act on any of the activities that may be delegated by the Board or the Governing Body.

18.2.13 To recommend to the Board appropriate actions against person(s) responsible for unauthorized expenditure and any financial irregularity.

18.2.14 To hold and manage the property and investments of the University including endowed tangible and intangible properties.

18.2.15 To frame Rules for Reciprocal Offer to the Donors, and recommend to the Board appropriate reciprocal offer to those who wish to endow their property to the University, like putting the donor's name plate on the property, reservation of certain number of seats in admission of a course or program, institution of medals, trophies, awards etc.

18.2.16 To ensure that the buildings, land, furniture, equipment and machinery are maintained up-to-date and that the stock-taking is carried out periodically as per the auditors' or bank's advice.

19.0 Selection committee

19.1 The Board of Management may appoint a selection committee to recommend names of the persons for the posts of Directorates, Directors, Associate Directors, Principals, Vice Principals, Deans, Associate Deans, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Readers, Senior Lecturers, Lecturers, Junior Lecturers, Research Fellows, Research Associates, Research

Assistants, Teachers, Teaching Assistants and such other academic posts as may be prescribed by to Board of Management.

19.2 The selection committee so appointed shall consist of:

i. The Vice- Chancellor – Chairman.

ii. Two experts in the relevant discipline(s) nominated by the Chancellor, and not connected with the University.

iii. One expert in the relevant discipline(s) nominated by the Vice-Chancellor.

iv. One Nominee of the Board of Management, who shall not be below the rank of a professor or who holds professional qualification and equivalent position in industry, business, service, profession or government.

20.0 Constitution of Standing Committee, Ad-hoc Committees and Enquiry Committees

20.1 The Governing Body and / or the Board of Management may by a resolution in a duly conducted meeting appoint standing committee or ad-hoc committee and / or enquiry committee by defining-

i. The purpose of appointment

ii. The constitution

iii. The tenure of the committee

iv. The financial budget

v. The procedure to be adopted

vi. The rights and obligations of the committee

vii. The facilities to be provided and

viii. Other matters relevant or incidental to complete the purpose for which it is appointed.

20.2 The committee(s) so appointed shall exercise their powers and functions within the delegated authority. Neither the University nor the Governing Body nor the Board of Management nor any other authority of the University shall be accountable for the authority or the powers used outside the scope of delegation by such committees.

20.3 Such committee shall be automatically dissolved on completion of their tenure or the tasks assigned to them by the said authority appointing them, unless the said authority grants extension in the tenure.

21.0 Advisory Committees

21.1 The Governing Body or the Management Board, with the concurrence of Chancellor or Vice- Chancellor, may appoint an advisory committee consisting of five members, for the purpose of rendering advice to it in matters relating to the conduct of affairs of the University or for such other purposes as it may prescribe from time to time.

21.2 The Advisory Committee(s) shall consist of eminent persons and may include the

members of the Governing Councils of the Faculties, Schools, "Colleges, Institutes, Research Centers, Centers of Excellence, Training Centers and Heads of Study Centers of the University.

21.3 The Board may direct the Academic Council, Finance Committee and / or any other committee set up under the Act or the Statutes to appoint an Advisory Committee and to consider and/or follow its recommendations.

21.4 The Board shall define the functions, powers and time period while establishing such committees.

22.0 General Fund

The University shall establish a fund which shall be called the General Fund to which shall be credited the following:

22.1 Any contribution made by the Sponsoring Body.

22.2 Fees and other charges received by the University.

22.3 Any income or surplus received from consultancy and other work undertaken by the University or its constituent or affiliated Faculties, Schools, Colleges, Institutes, Research Centers, Centers of Excellence, Training Centers and Study Centers in pursuance of its objectives.

22.4 Trusts, bequests, donations, endowments and any other grants.

22.5 All other sums received by the University.

22.6 The General Fund shall be used for the purposes enumerated in the Statutes and the Act.

23.0 Budget

23.1 The Chief Finance and Accounts officer, with the approval of the Finance committee, based on the proposed budgets received form different faculties, schools, colleges, institutes, study centers, training centers, research centers, centers of excellence of the University, shall prepare annual budget with periodic break-up for the forthcoming financial year, and submit at least two months before the beginning of financial year to the Board for the purposes of approving the same. The Board, upon the merits may suggest modifications, alterations or additions, and approve the same with or without modifications and such approved budget will be the annual budget of the University for the year.

23.2 The faculties, colleges, institutes and various centers, departments and officers and employees of the University, without the prior approval of the Finance Committee, shall incur no expenditure other than that provided in the budget.

23.3 The Finance Committee may consider any revision of the Budget based on the recommendations of the Chief Finance and Accounts officer and shall place the same for rectification with the Board at a subsequent meeting of the Board.

23.4 **Accounts and Audit**:

24.4.1 The Accounting year of the University shall be from 1st April of a year to 31st March of the following year, or as specified by the Central or State Government from time to time.

24.4.2 The accounts of various faculties, schools, colleges, institutions and campuses of the University shall be consolidated by the Chief Finance and Accounts Officer who shall prepare the final annual or periodic accounts as required under the law or by the Board, consisting of the Income and Expenditure Account and the Balance Sheet of the University and place the same before the Finance Committee for their comments. The Finance Committee shall decide the appropriations or absorptions of excess of income or expenditure. The accounts shall thereafter be adopted by the Governing Body after the Auditors appointed by the Governing Body audits them.

23.5 All the assets of the University shall be maintained in the name of the University and shall be used for the settlement of liabilities at the time of liquidation or closure of the University under sections 33 and 34 of the Act.

23.6 The accounts of the University shall be open to examination by the Chancellor, President, Vice-Chancellor, Registrar, Auditor of the University and any other person authorized by the Governing Body or the Sponsoring Body for the purpose.

23.7 Every Balance Sheet and Income and Expenditure account of the University shall comply with the relevant accounting standards as may be prescribed by the Government of India. Accounts of the institutes, schools, colleges, research centers, centers of excellence, training centers and study centers abroad shall comply with the relevant accounting standards as may be prescribed by the international accounting standards or the Government of the country in which such institution is located.

23.8 The President or the Vice-Chancellor with his consent shall place the audited financial statements before the Governing Body, along with the report of the Auditors for information.

23.9 The Chief Finance and Accounts Officer, thereafter along with the Annual Report of the University, shall submit such financial statements to the Visitor and the Government as provided under section 30 of the Act.

24.0 Arbitration in case of disputes

24.1 The Vice-Chancellor shall be responsible for resolution of disputes and grievances between the teachers, officers, other employees and the students of the University.

24.2 The Vice-Chancellor may delegate the responsibility for arbitration to the Registrar or the Deans as he may deem fit.

24.3 Any person who is aggrieved of the decision of the Vice-Chancellor may appeal to the Chancellor within 30 days of communication of the decision by the Vice-Chancellor.

24.4 Where found necessary, the Chancellor may appoint an Arbitration Committee to arbitrate such disputes and grievances.

24.5 The Arbitration Committee shall constitute the following:

(i) One representative of the Vice-Chancellor.

(ii) One representative of the aggrieved person.

(iii) A person nominated by the Chancellor as Chairman.

24.6 The Committee shall submit the Report to the Chancellor, and the Chancellor's decision shall be final.

25.0 Regulations and Manuals

25.1 Save as otherwise provided in the Act and the Statutes, the Board of Management may make Regulations, as empowered under section 37 of the Act, to conduct the administration and management affairs of the University and attain the objectives and the mission for which it is established. The Regulations may, interalia relate to the following:

25.1.1 Establishment or affiliation of Faculties, Schools, Colleges, Institutes, Training Centers, Research Centers, Centers of Excellence, Sports Complexes, Gardens, Entertainment Centers, Amusement and Water Theme Parks, Halls of Residence for Students, Staff Quarters, Professors / Officers Bungalows, Guest Houses, Roads etc as may be required to attract the best talent and promote the excellence in the University.

25.1.2 Establishment of Distance Education Study Centers or University / College Study Centers, Examination Centers, etc.

25.1.3 Establishment of Directorates for providing implementation and support services in Distance Education, Preparatory Services, Employment and Placement, Entrepreneurship Development, Women Education and Empowerment, Rural Upliftment & Development, etc.

25.1.4 The courses of study to be laid down for all degree, diploma and certificate programs of the University.

25.1.5 The grant of academic awards, distinctions, trophies etc.

25.1.6 Number of seats in different programs of the University, not otherwise prescribed for by any other statutory body authorized for the purpose.

25.1.7 Reservation of seats in different programs of the University not otherwise prescribed for by any other statutory body authorized for the purpose.

25.1.8 Admission of the students and their enrolment.

25.1.9 Fees and other charges payable by the students.

25.1.10 Examination and student assessment systems.

25.1.11 Award of scholarships, bursaries, fee waivers, etc. to students.

25.1.12 Discipline of students, of employees and outside visitors to the University and its constituents.

25.1.13 Resolution of disputes among students, employees etc. and procedure for arbitration.

25.1.14 Conferment of Honorary Degrees up to doctoral and post-doctoral levels to distinguished persons from India or abroad.

25.1.15 Finance, administration and management of the University.

25.1.16 The Board may appoint an ad-hoc committee(s) to draft the Regulations and to prepare manuals for different departments/ functions, faculties, schools, colleges, study centers, training centers, research centers, centers of excellence etc. of the University.

25.1.17 The committee(s) appointed as above, shall have such members as nominated by the Board and perform all the functions as required under the order of appointment / constitution.

25.2 On satisfying themselves on the Regulations made out by the committee(s) appointed for the purpose, the Board may adopt them for the University.

25.3 Each and every authority and officers, teaching and non-teaching employees, members of the committees and students are bound to adhere to the provisions and procedures laid down in the manual of instructions drafted for the purpose.

25.4 The Board shall have the right to alter, amend, frame new rules and regulations, which are not inconsistent with the provisions of the Act, for the purpose of conducting the affairs and activities of the University for which it is established.

25.5 The creation, composition and functions of any committees or body, which is considered necessary for the work of the University.

25.6 The preparation and submission of budget estimates.

25.7 The procedure for convening a meeting of any authority and the conduct of the same.

26.0 Interpretation

26.1 In the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules, the provisions of the Act shall prevail.

26.2 The decision of the Governing Body on interpretation shall be final and binding to all concerned.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/19/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सकराली प. ह. नं. 13	16.30	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	सकराली वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा-1, 2, 3.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/20/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भेड़ीकोना प. ह. नं. 13	13.49	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	सकराली वितरक नहर के शाखा एवं भेड़ीकोना मार्ग.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/21/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चुराघांठा प. ह. नं. 13	9.20	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	सकराली वितरक नहर के चुराघांठा माइ. 1, 2.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/22/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चुराघांठा प. ह. नं. 13	1.42	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	सकराली वितरक नहर के चुराघांठा माइ. 3.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/23/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प. ह. नं. 10	6.82	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	सकराली वितरक नहर के शाखा.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/24/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प. ह. नं. 10	0.61	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	सकराली वितरक नहर के चुराघांठा माइ. 1.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/25/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मेढ़ापाली प. ह. नं. 12	2.19	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइ. 1.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक क /भू-अर्जन/26/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बारापीपर प. ह. नं. 16	0.08	अनु. अधि., मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइ. 3.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 3/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कालाखूंटा प. ह. नं. 49	1.515	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	कालाखूंटा जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	केरमेली प. ह. नं. 48	2.189	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	कालाखूंटा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 5/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	पठियापाली प. ह. नं. 38	12.416	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	पठियापाली जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 16/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरवानी प. ह. नं. 39	1.641	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	सरवानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 17/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	झारगुड़ा प. ह. नं. 17	2.772	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झारगुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 18/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सिहा प. ह. नं. 37	3.352	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सिहा जलाशय हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 19/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	देवबहाल प. ह. नं. 17	0.870	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झारगुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 20/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोड़पाली प. ह. नं. 43	3.055	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोड़पाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 21/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कठानी प. ह. नं. 34	4.711	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोड़पाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 22/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोहाखान प. ह. नं. 34	7.647	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लोहाखान जलाशय योजना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.221 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6/3	0.004
	6/5	0.052
	7/1	0.117
	7/4	0.032
	7/3	0.004
	7/7	0.012
योग	6	0.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है-विंध्याचल स्टेज III के तहत 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक/क/अ.वि.अ./02 अ-82, 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प.ह.नं. 72/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159	0.01
161	0.45
162	0.04
211	0.10
214	0.14
221	0.23
222	0.03
223	0.03
224	0.03
225	0.03
226	0.10
227	0.03
228	0.04
775	0.04
229	0.03
230	0.15
231	0.10

(1)	(2)
232	0.07
233	0.13
234	0.12
235	0.09
236	0.02
251	0.14
237	0.02
253	0.13
255/2	0.08
288	0.04
238	0.02
259	0.07
267	0.06
239	0.02
247	0.12
248	0.08
250	0.47
252	0.26
262	0.22
258	0.05
260	0.04
261	0.15
308	0.09
311	0.17
263	0.07
264	0.08
265	0.18
266	0.08
268	0.01
776	0.15
269	0.13
282	0.22
270	0.01
281	0.07
283	0.30
285	0.30
284	0.99
304	0.06
289	0.01
303	0.27
306/1	0.06
306/2	0.04
306/3	0.10
307	0.04
309	0.14
312	0.11
313	0.18
314	0.40
777	0.41
305	0.19
310	0.05
योग 68	8.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रायपुर (माना) विमानतल के विस्तार हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2004

क्रमांक/क/वा./अ.वि.अ./10 अ-82, 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-गुल्लू, प.ह.नं. 57/41

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2475	0.42

(1)	(2)
2473/1	0.38
2560	0.11
2399	0.29
2730	0.16
2482	0.08
2486	0.14
2564	0.53
2561	0.25
2573	0.02
2563/3	0.19
2499	0.35
2472	0.09
2474	0.21
2514	0.45
1670/1	0.37
2661	0.05
2668	0.38
2562	0.57
2571	0.36
1672	0.88
2570	0.02
2481	0.94
1671/1	0.04
2729/1	0.17
1638	0.02
2572/1	0.12
2492	0.19
2573/2	0.23
2480	0.15
2396	0.24
1637	0.42
1673	0.16
1634/2	0.02
2491	0.10
2496	0.34
1680	0.02
2568	0.68
2497/2	0.02
2553	0.02
2473/2	0.03
2648	1.44
1667	0.51
1635	0.44
2493	0.07
2660	0.03
1670/2	0.78
2565	0.25
2494	0.07
1679	0.06
2675	0.18
2729/3	0.09
2572/2	0.20
2731	0.03
2726	0.24
2581	0.40
2400/2	0.04
2669	0.10
2495	0.56
1669/2	0.01
1678/2	0.13
2671	0.07
1677	0.50
1676	0.08
2513	0.20
2498	0.04
2580	0.58
2644	0.08
2673	0.02
2729/2	0.09
1669/1	0.18
2410	0.80
2415	1.20
1668	0.98
2625	0.50
योग 75	21.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेंटेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.